



# केन्द्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27: भारत के सेवा निर्यात को बढ़ावा

*भारत के मजबूत सेवा निर्यात प्रदर्शन का विस्तार*

14 मार्च 2026

## प्रमुख बिंदु

- वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल-जनवरी में सेवाओं का निर्यात 348.4 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया।
- वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में सेवाओं का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 प्रतिशत तक पहुंच गया।
- भारत के सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर सेवाओं का दबदबा रहा, जबकि व्यावसायिक और परामर्श सेवाएं प्रमुख विकास कारकों के रूप में उभरी हैं।
- केन्द्रीय बजट 2026-27 में विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कर छूट, भारत में स्थित बुनियादी ढांचे का उपयोग करके वैश्विक ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने, आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुधार और उन्नत मूल्य निर्धारण समझौतों (एपीए) में सुधार के प्रावधानों की घोषणा की गई है।
- वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) का विस्तार, एआई क्षमताओं और बेहतर वैश्विक बाजार पहुंच भारत के सेवा निर्यात में वृद्धि को गति दे रहे हैं।

## परिचय

भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सबसे सशक्त प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है, जो विकास, उत्पादकता और वैश्विक एकीकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवाओं की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर 49.9 प्रतिशत हो गई, जो महामारी से पहले के औसत से लगभग 1.5 प्रतिशत अंक अधिक है। यह वृद्धि वैश्विक औसत और अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक है। डिजिटल प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने और भारतीय कंपनियों के वैश्विक वैल्यू चेन में अधिक गहराई से एकीकृत होने के कारण उत्पादकता में सुधार से इस विस्तार को बल मिला है।

केंद्रीय बजट 2026-27 आईटी सेवाओं के लिए लक्षित कर सुधारों, क्लाउड और डेटा केंद्रों के लिए प्रोत्साहनों, सरलीकृत अनुपालन तंत्रों और व्यापार सुगमता उपायों के माध्यम से इस दिशा को और मजबूत करता है, जिसका उद्देश्य सेवा व्यापार में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इसमें भारत को सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने की परिकल्पना भी की गई है, जिसके तहत 2047 तक वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विकसित भारत के लिए एक उच्च स्तरीय 'शिक्षा से सशक्तिकरण और उद्यमशीलता'संबंधी स्थायी समिति की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

यह समिति विकास और रोजगार सृजन में सक्षम उच्च क्षमता वाले सेवा उपक्षेत्रों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह अंतर-क्षेत्रीय नीति और नियामक मुद्दों, जिनमें मानक और प्रत्यायन ढाँचे शामिल हैं, पर भी विचार करेगी और भारत के सेवा निर्यात को और अधिक बढ़ाने के रास्ते तलाशेगी। यह समिति रोजगार और कौशल पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का आकलन भी करेगी, साथ ही शिक्षा में एआई के एकीकरण, कार्यबल के कौशल उन्नयन और पुनःकौशल विकास, एआई-सक्षम नौकरी मिलान, अनौपचारिक कार्य के औपचारिककरण और वैश्विक प्रतिभा और कुशल प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने के उपायों का प्रस्ताव तैयार करेगी।

सेवा क्षेत्र के विकास के साथ, सेवा व्यापार भारत के बाह्य क्षेत्र के प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, और बदलते वैश्विक परिस्थितियों के बीच बढ़ते निर्यात समग्र व्यापार वृद्धि को समर्थन दे रहा है।

## भारत के सेवा निर्यात का प्रदर्शन और कारक

### विकास और हाल का प्रदर्शन

भारतीय सेवाओं की वैश्विक मांग में निरंतरता के चलते वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सेवा निर्यात ने मजबूत गति बनाए रखी है। अप्रैल-जनवरी 2025-26 की अवधि में सेवा निर्यात का अनुमान 348.4 अरब अमेरिकी डॉलर है।



### **आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का बढ़ता योगदान**

भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, सेवाओं का निर्यात भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में उभरा है, जो बाह्य कमजोरियों को कम करने और व्यापार स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। सेवाओं के निर्यात का बढ़ता महत्व समग्र आर्थिक गतिविधि में उनके बढ़ते योगदान में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

जीडीपी में बढ़ती हिस्सेदारी: वित्त वर्ष 2023-2025 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में भारत के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी औसतन 9.7 प्रतिशत रही, जो महामारी से पूर्व की अवधि के 7.4 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है और आर्थिक विकास को समर्थन देने में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में यह योगदान और मजबूत हुआ, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में सेवा निर्यात की हिस्सेदारी बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई, जो भारत के सेवा-आधारित विकास पथ के निरंतर विस्तार और लचीलेपन को दर्शाती है।

श्रम बाजार की स्थिरता को समर्थन: सेवा क्षेत्र रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्रोत भी बनकर उभरा है। यह कुल रोजगार का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है। पिछले छह वर्षों में, कोविड-19 के बाद के आर्थिक सुधार काल में इस क्षेत्र ने लगभग 40 मिलियन नौकरियां सृजित की हैं, जो श्रम बाजार में झटकों को सहन करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करता है।

### **सेवा निर्यात के विभागीय कारक**

आरबीआई के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं (आईटीईएस) पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वार्षिक आधार पर 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो भारत के डिजिटल सेवाओं के निर्यात में निरंतर गति को दर्शाती है। इस अवधि के दौरान, भारत के कुल सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं का हिस्सा दो-तिहाई से अधिक रहा, जबकि बीपीओ सेवाएं आईटीईएस निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण घटक बनी रहीं।

यह मजबूत प्रदर्शन भारत के सेवा क्षेत्र की व्यापक मजबूती को दर्शाता है, जिसे सॉफ्टवेयर, बीपीएम, परामर्श और फिनटेक क्षेत्रों के निरंतर विस्तार का समर्थन प्राप्त है, जो समग्र सेवा निर्यात को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। डिजिटल सेवाओं की मजबूत वैश्विक मांग के कारण, सॉफ्टवेयर सेवाएं सबसे बड़ा घटक बनी हुई हैं। यह कुल सेवा निर्यात का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और वित्त वर्ष 2023-2025 के दौरान औसतन 13.5 प्रतिशत की दर से इसका विस्तार हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2016-2020 में यह दर 4.7 प्रतिशत थी। इसके साथ ही, हाल के वर्षों में व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में तेजी आई है, जिससे भारत की बाह्य क्षेत्र की मजबूती में इस क्षेत्र का बढ़ता योगदान और भी पुष्ट हुआ है। वित्त वर्ष 2023-2025 में, व्यावसायिक और प्रबंधन परामर्श क्षेत्र दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता

के रूप में उभरा है, जिसमें 25.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप इसका योगदान वित्त वर्ष 2016-2020 में 10.5 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-2025 में 18.3 प्रतिशत हो गया है।



ये सभी क्षेत्र मिलकर सेवा निर्यात का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनाते हैं, जो सीमा पार और ज्ञान-आधारित गतिविधियों में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है।

## बजट में सेवा क्षेत्र पर जोर: अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

भारत ने खुद को सॉफ्टवेयर विकास, आईटी-आधारित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर सॉफ्टवेयर-संबंधित अनुसंधान एवं विकास सेवाओं में वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान स्थापित किया है। इस मजबूत वैश्विक स्थिति को देखते हुए, **केंद्रीय बजट 2026-27 में आईटी और आईटी-आधारित सेवा क्षेत्र के विकास को समर्थन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है।**

### डेटा सेंटर प्रोत्साहनों के माध्यम से क्लाउड सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा

केंद्रीय बजट की सबसे विशिष्ट पहलों में से एक भारत स्थित डेटा सेंटर अवसंरचना के माध्यम से संचालित वैश्विक क्लाउड सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनों की शुरुआत है। महत्वपूर्ण अवसंरचना को सक्षम बनाने और डेटा सेंटरों में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानते हुए, बजट में भारत में स्थित अवसंरचना का उपयोग करके वैश्विक ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कर छूट का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, भारत से

डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली संबंधित संस्थाओं को लागत पर 15 प्रतिशत के सुरक्षित लाभ मार्जिन से लाभान्वित होने का प्रस्ताव है।

### आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर संबंधी सुधार

---

केंद्रीय बजट में अनुपालन को सरल बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी-सक्षम सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और कांट्रैक्ट पर सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित अनुसंधान एवं विकास सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एक ही श्रेणी के अंतर्गत समेकित करने का प्रस्ताव है। इसमें 15.5 प्रतिशत का एक समान सेफ हार्बर मार्जिन होगा। साथ ही, आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सीमा को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सेफ हार्बर व्यवस्था को कर अधिकारी की आवश्यकता के बिना एक स्वचालित नियम-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा, और एक बार विकल्प चुनने के बाद, आईटी सेवा कंपनियां अपने विवेक पर लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए समान सेफ हार्बर प्रावधानों के तहत काम करना जारी रख सकेंगी।

### अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (एपीए) सुधार

---

बजट में आईटी सेवा कंपनियों के लिए, जो अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (एपीए) करना चाहती हैं, एकतरफा एपीए प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य 2 वर्षों के भीतर समझौते संपन्न करना है। करदाता के अनुरोध पर 2 वर्ष की अवधि को 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। एपीए में शामिल संस्थाओं को उपलब्ध संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा को उनकी संबद्ध संस्थाओं तक भी विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

# UNION BUDGET 2026-27: STRENGTHENING INDIA'S GLOBAL IT & SERVICES LEADERSHIP



## Cloud & Digital Infrastructure

Tax holidays till 2047

Global cloud services delivered from India

**15%** safe harbour for data centre entities

## Safe Harbour Reforms

Unified IT services category

**15.5%** safe harbour margin

Threshold raised:  
**₹300 Cr → ₹2,000 Cr**

Automated approval valid for 5 years

## APA & Dispute Resolution

Fast-tracked APA completion (2 years)

Extendable by 6 months

Source: Ministry of Finance

### एकतरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (यूएपीए)

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एकतरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (यूएपीए) एक करदाता और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बीच एक निश्चित अवधि के लिए निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के लिए लगाए जाने वाले मूल्य या उसके निर्धारण को अग्रिम रूप से निर्धारित करने के लिए किया गया समझौता है।

### सेवा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त बजट पहल

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में कौशल विकास के माध्यम से भारत के सेवा इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की गई हैं। इनमें से कुछ पारंपरिक चिकित्सा, चिकित्सा संबंधी यात्रा और पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं।

- **कुशल देखभालकर्ताओं का विकास:** वृद्धावस्था और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए एक मजबूत देखभाल प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। एनएसक्यूएफ (नेशनल क्वालिटी एंड टेक्निकल फैसिलिटी) के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे ताकि बहुकुशल देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा सके, जिनमें मुख्य देखभाल और संबद्ध कौशल, जैसे कि स्वास्थ्य, योग और

चिकित्सा एवं सहायक उपकरणों का संचालन शामिल हो। आगामी वर्ष में 1.5 लाख देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

### भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण

तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और दीर्घकालिक बीमारियों में वृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर देखभालकर्ताओं की मांग बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएलओ) के अनुसार, देखभाल सेवाओं में मौजूदा महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने से लगभग 3 करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में, **बजट 2026-27 में वृद्धावस्था और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए एक मजबूत देखभाल प्रणाली के विकास की घोषणा से भारत में देखभालकर्ता पेशेवरों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो इस वैश्विक मांग में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।**

- **आयुष:** भारत आयुष की वैश्विक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और **बजट 2026-27 में की गई घोषणाओं से उम्मीद है कि योग को आज जो व्यापक वैश्विक मान्यता प्राप्त है, उसी तर्ज पर चिकित्सा की इन पारंपरिक शाखाओं की वैश्विक स्वीकार्यता और मान्यता में वृद्धि होगी। निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:**
  - तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना
  - जामनगर में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन, जिससे पारंपरिक चिकित्सा के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।
  - उच्च मानकों के प्रमाणन तंत्र के लिए आयुष फार्मेशियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन
- **पर्यटन को बढ़ावा देना:** पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **चिकित्सा संबंधी यात्रा:** भारत को चिकित्सा संबंधी पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच चिकित्सा पर्यटन केंद्रों की स्थापना में सहयोग करेगी।
  - **गाइडों का कौशल विकास:** 20 प्रतिष्ठित स्थलों पर 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए एक पायलट योजना शुरू की गई है। इस पहल में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के सहयोग से विकसित 12 सप्ताह का हाइब्रिड प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।

- **पुरातात्विक स्थलों का विकास:** लोथल, सारनाथ और हस्तिनापुर सहित 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को विश्व स्तरीय अनुभव केंद्रों में विकसित करके विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। इस पहल का उद्देश्य पर्यटक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, सतत पर्यटन को बढ़ावा देना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर में एक नया बौद्ध सर्किट शुरू करना है।
- भारत की विश्व स्तरीय ट्रेकिंग और हाइकिंग अनुभव प्रदान करने की क्षमता और अवसर का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- पर्यटन कनेक्टिविटी के लिए हाई-स्पीड रेल: प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल मार्ग (मुंबई-पुणे; पुणे-हैदराबाद; हैदराबाद-बेंगलुरु; हैदराबाद-चेन्नई; चेन्नई-बेंगलुरु; बेंगलुरु-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी) का उद्देश्य प्रमुख व्यापारिक केंद्रों और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के बीच यात्रा के समय को संभावित रूप से कम करना है।

## सेवा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के नये कारक

### जीसीसी का बढ़ता असर

भारत के बढ़ते सेवा निर्यात को वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के एक प्रमुख केंद्र के रूप में देश के



उभरने से लगातार समर्थन मिल रहा है, जिनकी वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2025 के बीच लगभग 7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) रही। जीसीसी भारत से सीमा पार सेवाओं के वितरण का एक प्रमुख माध्यम बन गए हैं। वित्त वर्ष 2024 तक, भारत में 1,700 से अधिक जीसीसी हैं जिनमें 1.9 मिलियन से अधिक पेशेवर कार्यरत हैं, जिससे यह कैप्टिव वैश्विक संचालन का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र

बन गया है।

समय के साथ, जीसीसी सहायक कार्यों से विकसित होकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक संचालन के अभिन्न अंग बन गए हैं, जो उत्पाद विकास, एआई-सक्षम डिजिटल सेवाएं, साइबर सुरक्षा, विश्लेषण और इंजीनियरिंग जैसी उच्च-मूल्य वाली गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और भारत के ज्ञान-केन्द्रित और डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं। भारत में श्रम संबंधी

रियायत, मजबूत भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे, लागत प्रतिस्पर्धा, एसईजेड से जुड़े प्रोत्साहन और एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उनके विस्तार को समर्थन दिया है, ये सभी कारक समग्र दक्षता को बढ़ाते हैं।

## भारत का एआई और डिजिटल इकोसिस्टम

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताएं निर्यात में इस वृद्धि को और मजबूत करती हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, एआई कौशल पैठ में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो वैश्विक सेवा वितरण में सहायक उन्नत डिजिटल प्रतिभा की उपलब्धता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भारत की तकनीकी तत्परता में सुधार को उजागर करते हैं, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र परिषद विकास संगठन (यूएनसीडीएडी) के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस इंडेक्स में देश

2022 में 48वें स्थान से 2024 में 36वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, भारत क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं में अग्रणी देशों में शुमार है, जिसे विश्व की सबसे बड़ी आबादी में से एक का समर्थन प्राप्त है, जो एआई डेवलपर्स के एक महत्वपूर्ण समूह का लाभ उठा सकती है।

डेटा की खपत, क्लाउड को अपनाने और एआई के उपयोग में तीव्र वृद्धि से डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश में तेजी आ रही है। अनुमान है कि भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2025 में लगभग 1.4 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक लगभग 8 गीगावाट हो जाएगी। यह विस्तार वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से सक्षम सेवाएं प्रदान करने की भारत की क्षमता को मजबूत करता है। देश के बढ़ते नवाचार इकोसिस्टम का प्रतिबिंब एआई स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या, उद्यम निवेश और जनरेटिव एआई पेटेंट दाखिल करने की विश्व स्तर पर सबसे तेज वृद्धि दर में से एक में दिखाई देता है।

## वैश्विक व्यापार समझौतों से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा

भारत के बढ़ते व्यापार समझौतों के नेटवर्क ने वैश्विक बाजारों में सेवा क्षेत्र की पहुंच को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समझौते पेशेवरों के लिए अधिक सक्रियता और भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं में नए अवसर प्रदान करते हैं।



## भारत-ब्रिटेन (सीईटीए)

---

- **विस्तारित बाजार पहुंच:** ब्रिटेन ने आईटी/आईटीईएस, व्यावसायिक सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, वित्तीय, दूरसंचार और शिक्षा सेवाओं जैसे भारत के हित के क्षेत्रों में 137 उप-क्षेत्रों में समग्र और गहन बाजार पहुंच प्रदान की है।
- **भारतीय पेशेवरों के लिए आसान पहुंच:** भारतीय पेशेवरों को सरलीकृत वीजा प्रक्रियाओं और उदार बनाई गयी प्रवेश श्रेणियों से लाभ होगा, जिससे ब्रिटेन में काम करना आसान हो जाएगा। इन पेशेवरों को कंपनियों ब्रिटेन में सभी सेवा क्षेत्रों में काम करने के लिए तैनात करती हैं और वास्तुकार, इंजीनियर, शेफ, योग प्रशिक्षक और संगीतकार जैसे संविदात्मक पेशेवरों को भी नियुक्त करती हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा पर समझौता:** सीईटीए पर हस्ताक्षर के दौरान दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर भी सहमति व्यक्त की, जो सीईटीए के साथ ही लागू होगा। इसी के अनुरूप, सामाजिक सुरक्षा अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौते पर दोनों देशों ने 10 फरवरी 2026 को हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एक-दूसरे के क्षेत्रों में 36 महीने तक की अस्थायी नियुक्तियों पर तैनात दोनों देशों के कर्मचारियों के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचना है।

सामाजिक सुरक्षा अंशदान पर समझौता, साथ ही सीईटीए में गतिशीलता और बाजार पहुंच संबंधी प्रतिबद्धताओं से दोनों देशों के उच्च कौशल और नये सेवा क्षेत्रों का लाभ उठाते हुए सेवा क्षेत्र में भारत-ब्रिटेन साझेदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

## भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

---

- **विस्तारित बाजार पहुंच:** यूरोपीय संघ ने आईटी/आईटीईएस और पेशेवर सेवाओं सहित 144 सेवा उपक्षेत्रों में प्रतिबद्धताओं का विस्तार किया है, जिससे भारतीय प्रदाताओं को निर्यात बढ़ाने और दोनों अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार, उत्पादकता और व्यावसायिक विकास को समर्थन देने में मदद मिलेगी।
- **गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा सहायता:** भारतीय आयुष चिकित्सकों की यूरोपीय संघ में सक्रियता, भारतीय छात्रों की यूरोपीय संघ में गतिशीलता और भारत तथा यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाए रखने/निष्पादित करने/अपनाने के लिए भी सहायक प्रावधान किए गए हैं। भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)

## भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)

---

- **विस्तारित बाजार पहुंच:** ओमान ने पेशेवर सेवाओं, कंप्यूटर और संबंधित सेवाओं तथा ऑडियो-विजुअल सेवाओं सहित 127 सेवा उपक्षेत्रों में संकल्प दिखाया है। किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में पहली बार, ओमान ने अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आईटी,

शिक्षा, निर्माण और परामर्श सेवाओं सहित पेशेवरों की एक परिभाषित श्रेणी के लिए प्रतिबद्धता जताई है। स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है।

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की अधिकतम सीमा में विस्तार: इंटर-कॉर्पोरेट ट्रांसफरिज (आईसीटी) की अधिकतम सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे भारतीय कंपनियों को अधिक संख्या में प्रबंधकीय और विशेषज्ञ कर्मियों को तैनात करने का मौका मिलेगा।



## Global Trade Agreements Boosting Services Exports



**India-UK CETA:**  
Market access in **137** sub-sectors;  
Agreement on Social Security signed

**India-EU FTA:**  
**144** services subsectors covered

**India-Oman CEPA:**  
**127** services subsectors covered

**India-New Zealand FTA:**  
Commitment across  
**118** services subsectors

**India-EFTA TEPA:**  
Services Subsector Commitments:  
Switzerland (**128**), Norway (**114**),  
Liechtenstein (**107**), Iceland (**110**)

**India-Australia ECTA:**  
Commitment across  
**135** services subsectors

**CECPA with Mauritius:**  
Access to **115** services subsectors

Source: Ministry of Commerce & Industry

### भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता(एफटीए)

- **विस्तारित बाजार पहुंच:** न्यूजीलैंड ने 118 सेवा क्षेत्रों में प्रतिबद्धता जताई है। आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के व्यापार को भारत के साथ बढ़ावा देने और भारतीय छात्रों के लिए सक्रियता और अध्ययन के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सुगम प्रावधान शामिल किए गए हैं।

- **कुशल भारतीयों के लिए वीजा सुविधा:** न्यूजीलैंड ने भारत के लिए रुचि के क्षेत्रों में 3 वर्ष तक के प्रवास के लिए कुशल भारतीयों को 5,000 वीजा का कोटा देने की प्रतिबद्धता जताई है।

ये प्रावधान भारतीय युवाओं और पेशेवरों को वैश्विक अनुभव प्राप्त करने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करते हैं।

### **भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)**

- **विस्तारित बाजार पहुंच:** टीईपीए के तहत, स्विट्जरलैंड ने 128 उप-क्षेत्रों, नॉर्वे ने 114, लिक्टेन्स्टीन ने 107 और आइसलैंड ने 110 उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धता जताई है। यह अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की प्रतिबद्धता भी प्रदान करता है।

- **वृहत सक्रियता प्रावधान:** ईएफटीए ने कांट्रैक्ट पर सेवा आपूर्तिकर्ताओं और स्वतंत्र पेशेवरों के अंतर्गत कई सेवा क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में सक्रियता संबंधी प्रतिबद्धताएं प्रदान की हैं।

- **पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) :** नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और वास्तुकला जैसी पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) लागू किए गए हैं।

### **भारत आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (भारत-आस्ट्रेलिया ईसीटीए)**

---

- **विस्तारित बाजार पहुंच:** ईसीटीए के तहत, ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 135 उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं प्रदान की हैं।

- **बेहतर सक्रियता प्रावधान:** ऑस्ट्रेलिया ने इंटर-कॉर्पोरेट ट्रांसफर्रीज, कांट्रैक्ट वाले सेवा आपूर्तिकर्ताओं और स्वतंत्र अधिकारियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अस्थायी प्रवेश और अस्थायी प्रवास (4 वर्ष तक) की प्रतिबद्धताओं का विस्तार किया है। इसके अलावा, व्यावसायिक आगंतुकों और इंस्टॉलर एवं सर्विसर्स के लिए भी प्रतिबद्धताएं की गई हैं। भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक का पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा भी प्रदान किया जाएगा।

- **ऑफशोर कर राहत:** आईईसीटीए के तहत समझौते के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने उसे तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों की ऑफशोर आय पर कराधान को रोकने के लिए अपने घरेलू कराधान कानून में संशोधन किया है। इससे भारतीय तकनीकी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिली है।

### **मॉरीशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौता**

---

यह समझौता भारतीय सेवा प्रदाताओं को प्रमुख सेवा उद्योगों के लगभग 115 उपक्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे अवसरों का विस्तार होता है और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग मजबूत होता है।

### **वैश्विक निवेश से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मिल रहा**

भारत के सेवा क्षेत्र में बढ़ते विदेशी निवेश से वैश्विक क्षमता केंद्रों के तीव्र विस्तार और गहन अंतरराष्ट्रीय व्यापार साझेदारियों को समर्थन मिल रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थिति मजबूत हुई है।

वित्त वर्ष 2023-वित्त वर्ष 2025 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का औसत 80.2 प्रतिशत रहा, जो महामारी से पहले की अवधि के 77.7 प्रतिशत से अधिक है। यह भारत के सेवा निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। निवेश सूचना और संचार सेवाओं (25.8 प्रतिशत) और पेशेवर सेवाओं (23.8 प्रतिशत) में केंद्रित रहा है, जो डिजिटल और ज्ञान-आधारित गतिविधियों में भारत की मजबूती को दर्शाता है।

ये क्षेत्र इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वैश्विक साझेदारियों द्वारा समर्थित डिजिटल रूप से सक्षम और ज्ञान-आधारित सेवाएं, भारत के बढ़ते सेवा निर्यात के अनुरूप विदेशी निवेश को कैसे बढ़ावा दे रही हैं।

## **निष्कर्ष**

हाल के वर्षों में भारत के सेवा निर्यात में मजबूत और निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश के बाह्य क्षेत्र के प्रदर्शन के सबसे मजबूत कारकों में से एक के रूप में उभरा है। इसी कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय बजट 2026-27 लक्षित कर सुधारों, डिजिटल अवसंरचना प्रोत्साहनों, कौशल विकास पहलों और भारत के सेवा क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए उपायों के माध्यम से सेवा निर्यात वृद्धि को और अधिक सुदृढ़ कर रहा है।

प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक साझेदारियों के मेल से, भारत का सेवा क्षेत्र देश की विकास गाथा को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए तैयार है।

## **संदर्भ**

### **वित्त मंत्रालय**

<https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>

[https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget\\_speech.pdf](https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf)

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219981&reg=3&lang=2>

<https://incometaxindia.gov.in/Rules/Income-Tax%20Rules/10312000000007832.htm>

[https://www.indianembassyusa.gov.in/pdf/advance\\_pricing\\_agreement\\_guidance\\_with\\_faqs\\_\(tpi-43\).pdf](https://www.indianembassyusa.gov.in/pdf/advance_pricing_agreement_guidance_with_faqs_(tpi-43).pdf)

<https://incometaxindia.gov.in/Rules/Income-Tax%20Rules/10312000000007189.htm>

## **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2228785&reg=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219146&reg=3&lang=1>

<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/dec/doc20251218737701.pdf>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2207583&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2173138&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1812730&reg=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1708794&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2220413&reg=3&lang=2>

<https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2026/03/FTAs-achievement.pdf>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=156654&ModuleId=3&reg=3&lang=2>

## **भारतीय रिजर्व बैंक**

<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1208964F52A6DCBA464A91D091157FBCEC65.PDF>

<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR14286754E6C89EA04E6FBCE6626CE3CDF389.PDF>

<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR21919AC9681140584EFDB0D359321C6149A5.PDF>

## **अंतरराष्ट्रीय संस्थान**

<https://www.imf.org/en/news/articles/2026/01/28/cf-business-growth-and-innovation-can-boost-indias-productivity>

[https://unctad.org/system/files/official-document/tir2025ch3\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/tir2025ch3_en.pdf)

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099112525160536089/pdf/P505350-59c98ca8-0803-4f23-b470-17f3dab010ab.pdf>

<https://financing.desa.un.org/sites/default/files/2024-10/CRP%2024%20APA%20FAQs%20Appendix%20A%20.pdf>

<https://www.ilo.org/publications/major-publications/care-work-investing-care-leave-and-services-more-gender-equal-world-work>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एमएस